

मेसर्स ओजस इंडस्ट्रीज (पी) लिमिटेड

मेसर्स औध शुगर मिल्स लिमिटेड और आरैर अन्य

अप्रैल 2,2007

[डॉ. अरिजीत पसायत और एस. एच. कपाडिया, जे. जे.]

औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951-धारा 29 बी(1)-गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 गन्ना (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2006 द्वारा संशोधित-खंड 6ए, 6बी, 6सी, 6डी और 6ई-अधिनियम के तहत चीनी उद्योग को डी-लाइसेंस करने की अधिसूचना जारी-मौजूदा और प्रस्तावित चीनी कारखाने के बीच निर्धारित दूरी की आवश्यकता-दो औद्योगिक उद्यमी जापन (आईईएम) दो उद्यमियों द्वारा केंद्र सरकार के साथ अपनी चीनी मिलें स्थापित करने का प्रस्ताव निर्धारित सीमा के भीतर दूरी की आवश्यकतानुसार दायर किया गया-केंद्र सरकार ने पहले दायर किए गए आईईएम को मंजूरी दी और बाद में दायर आईईएम को खारिज कर दिया-केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली बाद के आईईएम धारक द्वारा लिखित याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई थी जिसमें कहा गया था कि निर्धारित दूरी की आवश्यकता मौजूदा और प्रस्तावित चीनी कारखाने के बीच है न कि दो प्रस्तावित चीनी कारखानों के बीच-संशोधन आदेश में दो प्रस्तावित चीनी कारखानों के बीच भी दूरी की आवश्यकता

निर्धारित की गई है और अनुमोदित आईईएम धारक के लिए निर्धारित अवधि के भीतर प्रभावी कदम उठाने के लिए शर्तें स्थापित की गई हैं- संशोधन आदेश की पूर्वव्यापी प्रयोज्यता-अभिनिर्धारित किया, दूरी की आवश्यकता निर्धारित करने का उद्देश्य गन्ने की अनुशासित खरीद और चीनी कारखानों को गन्ने की पर्याप्त आपूर्ति करना-संशोधन आदेश केंद्र सरकार द्वारा कई मुकदमों को समाप्त करने के लिए और आदेश में खामियों को दूर करने के लिए पेश किया गया है-इसलिए, संशोधन आदेश स्पष्ट है और पूर्वव्यापी रूप से लागू होता है।

केंद्र सरकार ने धारा 298(1) औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत एक अधिसूचना चीनी उद्योग को लाइसेंस मुक्त करने के लिए जारी की। इसके तहत न्यूनतम 15 किलोमीटर की रेडियल दूरी एक मौजूदा चीनी फैक्ट्री और एक प्रस्तावित चीनी फैक्ट्री से चीनी मिलों के बीच गन्ने की खरीद के लिए अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए निर्धारित की गई। अपीलार्थी-कंपनी ने चीनी मिल स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार के साथ औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आईईएम) दायर किया। इसके बाद, प्रत्यर्थी- कंपनी ने ऐसे स्थान पर चीनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए अपना आईईएम भी दाखिल किया, जो अपीलार्थी की प्रस्तावित चीनी फैक्ट्री से केवल 7.2 किलोमीटर दूर है। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी द्वारा दायर आई. ई. एम. को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष एक

रिट याचिका दायर की। प्रत्यर्थी ने उसी प्रार्थना के लिए अपीलार्थी के विरुद्ध एक रिट याचिका भी दायर की। उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को पक्षों के बीच विवाद पर गौर करने का निर्देश देकर दोनों रिट याचिकाओं का निपटारा कर दिया। केंद्र सरकार ने अपीलार्थी द्वारा दायर आईईएम को मंजूरी दी और प्रत्यर्थी द्वारा दायर आईई एम को अस्वीकार कर दिया। प्रतिवादी ने केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि अधिसूचना में निर्धारित न्यूनतम रेडियल दूरी केवल एक मौजूदा चीनी कारखाना और एक प्रस्तावित चीनी कारखाना के बीच है, न कि दो प्रस्तावित चीनी कारखानों के बीच। हालांकि, उच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार अधिसूचना में संशोधन करने के लिए स्वतंत्र है और दोनों प्रस्तावित कारखानों के बीच न्यूनतम रेडियल दूरी की आवश्यकता भी निर्धारित करती है।

केंद्र सरकार ने गन्ना (नियंत्रण)(संशोधन) आदेश, 2006 में गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 में खंड 6ए से 6ई सम्मिलित कर जारी किया। आदेश के खंड 6ए में प्रावधान किया गया है कि कोई भी नई चीनी फैक्ट्री किसी भी मौजूदा चीनी कारखाने के 15 किलोमीटर के दायरे में या अन्य नये चीनी कारखाने एक राज्य या दो या दो से अधिक राज्यों में स्थापित नहीं की जाएंगे। संशोधन आदेश में आगे प्रावधान किया गया है कि एक

नए चीनी कारखाने का अर्थ एक चीनी कारखाने से होगा जिसने आई ई एम. दाखिल किया है और निर्धारित समय के भीतर आई. ई. एम. के कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार के साथ एक करोड़ रुपये की प्रदर्शन गारंटी प्रस्तुत की है। संशोधन आदेश में यह भी प्रावधान किया गया है कि एक मौजूदा चीनी कारखाने में एक चीनी कारखाना भी शामिल होगा जिसने चीनी कारखाने की स्थापना के लिए संशोधन आदेश के स्पष्टीकरण 4 से 6 ए में निर्दिष्ट सभी प्रभावी कदम उठाए हैं।

इस न्यायालय में अपील में, अपीलार्थी ने तर्क दिया कि दूरी मौजूदा चीनी कारखानों से आवश्यकता अक्षम मौजूदा चीनी कारखानों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है जिसका इरादा चीनी उद्योग को लाइसेंस रद्द करने का नहीं था; कि इससे चीनी में नए निवेश को हतोत्साहित किया जाएगा और यह उदारीकरण की नीति की हताशा होगी; कि, यदि उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा जाता है, तो एक दूसरे के करीब कितनी भी चीनी कारखाने स्थापित किए जाएंगे, जिससे गन्ने की मांग इसकी आपूर्ति से बहुत अधिक हो जाएगी; कि आईईएम धारकों के बीच न्यूनतम दूरी भी रखी जानी चाहिए ताकि कच्चे माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके; कि बाद के आईईएम को तब तक सस्पेंस में रखा जाना चाहिए जब तक निर्धारित अवधि को पूरा होने के दौरान पहले आईईएम धारक प्रभावी कदम उठाएं; और जब पहले आईईएम धारक द्वारा प्रभावी कदम उठाए जाते

हैं, तो बाद वाले आईईएम गैर-अनुमानित हो जाएंगे।

उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि गन्ना (नियंत्रण) संशोधन आदेश प्रभाव में संभावित है और पूर्वव्यापी नहीं हो सकता क्योंकि यह निर्धारित करता है नई शर्तें जैसे कि बैंक गारंटी दाखिल करना, दूरी प्रमाण पत्र दाखिल करना और आईईएम को लागू करने के प्रभावी कदम; संशोधन से पहले कारखाना और एक प्रस्तावित चीनी कारखाना, न कि दो प्रस्तावित चीनी के बीच आईईएम दाखिल करने वाले कारखाने।

अपीलों और स्थानांतरण याचिकाओं का निपटारा करते हुए, न्यायालय

अभिनिर्धारित किया: 1.1. चीनी उद्योग को लाइसेंस मुक्त करने का उद्देश्य चीनी का उत्पादन बढ़ाना है। इसका उद्देश्य चीनी उद्योग को दुनिया में प्रतिस्पर्धी बनाना है। उद्देश्य गन्ने की निरंतर आपूर्ति है, उद्यमी व्यवहार्य क्षमता के नए चीनी संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव कर रहे हैं। उद्देश्य मिलों को गन्ने की अनुशासित खरीद और पर्याप्त आपूर्ति है। यदि चीनी मिलों को नजदीक में स्थापित करने की अनुमति दी गई तो गन्ने की मांग आपूर्ति की तुलना में बहुत अधिक हो जाएगी और ऐसी स्थिति में मौजूदा चीनी मिलों में गन्ने की कमी हो जाएगी और वे अव्यवहार्य हो जाएंगी, जिसके परिणामस्वरूप किसानों को भी नुकसान होगा।[पैरा 16] [673-एफ-जी]

**1.2. गन्ना (नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, 2006** सभी मामलों में पूर्वव्यापी रूप से लागू होगा, जिसमें वर्तमान मामले भी शामिल हैं जिनमें आई. ई. एम. लंबित हैं। आर्थिक कारणों से "दूरी" की इस अवधारणा को बरकरार रखा जाना चाहिए। यह अवधारणा मांग और आपूर्ति पर आधारित है। इस अवधारणा को बनाए रखना होगा क्योंकि संसाधन, अर्थात् गन्ना, सीमित है। "दूरी" का तात्पर्य किसान द्वारा चीनी मिल को आपूर्ति की जाने वाली गन्ने की उपलब्ध मात्रा से है। आदेश के तहत, एक उद्यमी जो वास्तव में चीनी मिल स्थापित करने में रुचि रखता है, उसे 1 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी देकर अपनी प्रामाणिकता साबित करनी होती है। इसके अलावा, बैंक गारंटी देना भी इस बात का प्रमाण है कि व्यवसायी के पास चीनी मिल स्थापित करने की वित्तीय क्षमता है और इसका दूरी प्रमाणपत्र से कोई लेना-देना नहीं है। गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खंड 6 में खंड 6ए से 6ई पेश किए गए प्रकृति में स्पष्टीकरणात्मक हैं। प्रभावी आदेश के खंड 6ए के स्पष्टीकरण 4 में सूचीबद्ध चरण अंतर्निहित मानदंड हैं: जिन्हें स्पष्ट किया गया है। इसलिए संशोधन आदेश के खंड 6ए का स्पष्टीकरण 4 स्पष्टीकरणात्मक है और पूर्वव्यापी है। [पैरा 18] [674-ई-जी; 675-बी-सी]

**1.3. केंद्र सरकार ने संशोधन आदेश मुकदमों का अंत अाैर खामियों को दूर करने के लिए जारी किया है। इसलिए, आदेश पूर्वव्यापी है।**

सभी लंबित मामलों में, केंद्र सरकार एक सीमित अवधि के लिए नई चीनी मिल स्थापित करने के लिए एक प्रतिबंध लगाना चाहती है, जिसके दौरान पूर्व आईईएम धारक काे प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। संशोधन आदेश नई इकाइयों की स्थापना पर प्रतिबंध नहीं लगा रहा है। यह केवल नई इकाइयों की स्थापना के मामले में प्राथमिकता दे रहा है। इसलिए, आदेश पूर्वव्यापी रूप से लागू होता है। संशोधन आदेश केवल उन मामलों पर लागू होता है जहां आई. ई. एम. विभिन्न अदालतों में विवादों में लंबित हैं। [ पैरा 18] [675-ई-जी]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: 2007 की सिविल अपील सं. 1730।

उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के रिट याचिका (सी) संख्या 7123/2005 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 22.12.2005 से

साथ

सी.ए.संख्या 1731-1735/2007.टी.पी.©न.421/2006,टीपी©न. 623/2006.

मोहन परासरन, एएसजी, मुकुल रोहतगी, वी. ए. मोहता, गौरव बनर्जी, शांति भूषण, सोली जे. सोराबजी, टी. आर. अंधियारुजना, जयंत भूषण, विवेक के. तन्खा, हरीश एन. साल्वे, अरुण जेटली, राकेश द्विवेदी, ए. एम. सिंघवी और राजीव दत्ता, भार्गव देसाई, उदय कुमार, संजीव कुमार

सिंह, हिना रिजवी, सैयद शाहिद हुसैन रिजवी, अखिलेश कालरा, महेश अग्रवाल, गौरव गोयल, अंकुर चावला, संजीव कुमार, विक्रम बजाज (मेसर्स खेतान एंड कंपनी के लिए), अंकुर शर्मा, निखिल मजोथिया, जोसेफ पूकट, प्रशांत कुमार, राजीव दुबे, कमलेंद्र मिश्रा, ई. सी. अग्रवाल, वी. के. वर्मा, सुमित गोयल, गौरव भाटिया, एस. वसीम ए. कादरी, कुश चतुर्वेदी (पी. एच. पारेख एंड कंपनी के लिए), प्रवीण कुमार, नवीन प्रकाश, डब्ल्यू. ए. कादरी, चिदानंद डी. एल., विजय गोयल, आर. एस. राणा, वी. के. वर्मा, भार्गव देसाई, गौरव भाटिया, विजयलक्ष्मी मेनन, इंदु मल्होत्रा, संजीव आनंद, सतीश विग, पारिजात सिन्हा और माणिक करंजावाला उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

कापडिया, जे. 1. विशेष इजाजत के लिए याचिकाओं में अनुमति दी जाती है।

2. मामलों के इस समूह में हमें चीनी उद्योग के लाइसेंस रद्द करने के संबंध में भारत सरकार, उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस नोट संख्या 12 दिनांक 31.8.1998 की व्याख्या करने की आवश्यकता है।

3. सुविधा के लिए हम 2007 की अपील सं. 1730 से उत्पन्न 2006 की एस.एल.पी.(सी) संख्या 7690 - मेसर्स ओजस इंडस्ट्रीज (पी)



लिमिटेड बनाम मेसर्स औध शुगर मिल्स लिमिटेड और अन्य में घटित तथ्यों को बताते हैं।

4. प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों का प्रसार विवाद का कारण है।

5. दिनांक 31.8.98 को भारत सरकार (संक्षेप में, 'भारत सरकार') ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (संक्षेप में, '1951 अधिनियम') के तहत चीनी उद्योग को अनिवार्य लाइसेंस से हटाने का निर्णय लिया। उस प्रेस नोट संख्या 12 में, भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि गन्ने की खरीद के लिए चीनी मिलों के बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए, मौजूदा चीनी मिल और नई मिल (फैक्ट्री) के बीच न्यूनतम 15 किलोमीटर की दूरी रखनी होगी। इसके अलावा, जो उद्यमी चीनी उद्योग की डी-लाइसेंसिंग का लाभ उठाना चाहता है, उसे उद्योग मंत्रालय के साथ एक औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (संक्षेप में, 'आईईएम') दाखिल करना आवश्यक था। उक्त प्रेस नोट में यह स्पष्ट किया गया था कि जिन उद्यमियों को चीनी के निर्माण के लिए आशय पत्र (संक्षेप में, 'एलओआई') जारी किया गया है, उन्हें प्रारंभिक आईईएम दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है और ऐसे मामलों में, एलओआई धारकों को वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के समय आईईएम का केवल भाग 'बी' दाखिल करना होगा।

6. दिनांक 11.9.98 की अधिसूचना उक्त 1951 अधिनियम की धारा

29बी(1) के तहत जारी की गई थी। इसे प्रेस नोट संख्या 12 दिनांक 31.8.98 के साथ पढ़ा जाना था। इसे डी-लाइसेंसिंग की नीति शुरू करने के लिए जारी किया गया था।

7. डी-लाइसेंसिंग के बाद जुलाई 2005 तक 2232 आईईएम दाखिल किए गए, जिनमें से 600 आईईएम यूपी में दाखिल किए गए।

8. दिनांक 13.5.04 को मै. ओजस इंडस्ट्रीज (पी) लिमिटेड (संक्षेप में, 'ओजस') ने गांव बैसागापुर, जिला लखीमपुर खीरी, यूपी. में एक चीनी मिल स्थापित करने के लिए अपना आईईएम दाखिल किया। इसे भारत सरकार द्वारा स्वीकार किया गया। ओजस का दावा है कि उसने जमीन खरीदने की अनुमति यूपी ज़मींदारी उन्मूलन और भूमि विनियमन अधिनियम के तहत ले ली है। इसका दावा है कि उसने फरवरी 2005 में मेसर्स एस.एस. इंजीनियर्स, पुणे से पूरे संयंत्र और मशीनरी के लिए ऑर्डर दे दिए हैं। इसका दावा है कि उसने फैक्ट्री भवन के निर्माण के लिए 8.65 करोड़ रुपये का ऑर्डर दिया है। यह 20 करोड़ रुपये से अधिक के खर्चों को पूरा करने के लिए बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ वित्तीय गठजोड़ करने का भी दावा करता है। इसका दावा है कि उसने यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी दिनांक 28.4.05 देने हेतु संपर्क किया है। उसका दावा है कि उसने ऐसी एनओसी हासिल कर ली है। ओजस ने विभिन्न अन्य मदों में 20 करोड़ रुपये खर्च करने का दावा किया है। चार दिन बाद

दिनांक 17.5.04 को मै. औध शुगर मिल्स लिमिटेड (संक्षेप में, 'औध') ने गांव सैदपुर, खुर्द, जिला लखीमपुर खीरी, यू.पी. बसैगापुर में ओजस की प्रस्तावित चीनी मिल से 7.2 किलोमीटर के भीतर में एक चीनी मिल (कारखाना) स्थापित करने के लिए अपना आईईएम दाखिल किया। इससे दोनों कंपनियों के बीच विवाद शुरू हो गया है।

9. 23.4.05 को ओजस ने औध द्वारा दायर आईईएम को रद्द करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी रिट याचिका संख्या 7123/05 दायर की। 28.5.05 को औध ने मेसर्स बजाज हिंदुस्तान लि. द्वारा तितारपुर में चीनी मिल स्थापित करने के लिए दायर आईईएम को रद्द करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका संख्या 9892/05 दायर की।

10. 30.6.2005 को, दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार, मामले की सुनवाई मुख्य निदेशक, चीनी, (भारत सरकार) द्वारा की गई, जिन्होंने ओजस द्वारा दायर आईईएम को मंजूरी दे दी। औध द्वारा दायर आईईएम को अस्वीकार कर दिया गया था। मुख्य निदेशक, चीनी, (भारत सरकार) के निर्णयों से व्यथित होकर, औध ने रिट याचिका संख्या 11748/05 दायर की। 26.7.05 को औध ने मेसर्स बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड के ग्राम खंबरखेड़ा में अपनी चीनी मिल स्थापित करने के लिए आईईएम को चुनौती देते हुए एक और रिट याचिका संख्या 12078/05

दायर की।

11. जैसा भी हो, दिनांक 22.12.05 के आक्षेपित निर्णय द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने माना कि दिनांक 11.9.98 की अधिसूचना प्रेस नोट संख्या 12 दिनांक 31.8.98 के साथ पढ़े जाने पर मौजूदा चीनी मिल और एक नई चीनी मिल के बीच की दूरी 15 किलोमीटर औंध के पूर्वाग्रह के लिए काम नहीं करती थी और यह कि औंध या किसी अन्य व्यक्ति के लिए मौजूदा चीनी मिल के 15 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर एक चीनी मिल स्थापित करने के लिए खुला था। यह माना गया कि केंद्र सरकार के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 73 के तहत उक्त प्रेस नोट No.12 जारी करने की कार्यकारी शक्तियां थीं। आगे यह माना गया कि उक्त प्रेस नोट, हालांकि, केवल उन मामलों पर लागू होता है जहां मौजूदा चीनी मिल के 15 किलोमीटर के भीतर एक नई मिल (कारखाना) स्थापित करने का प्रस्ताव है। आक्षेपित निर्णय के अनुसार, इसलिए, मौजूदा चीनी मिल की अनुपस्थिति में उक्त प्रेस नोट संख्या 12 दिनांक 31.8.98 का कोई उपयोग नहीं था। इसलिए, तथ्यों के आधार पर, यह माना गया कि ओजस उक्त प्रेस नोट संख्या 12 दिनांक 31.8.98 से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इन परिस्थितियों में, आक्षेपित निर्णय द्वारा यह माना गया है कि उक्त प्रेस नोट केवल तभी लागू होता है जब कोई मौजूदा चीनी मिल हो। तदनुसार, औंध द्वारा दायर आईईएम को रद्द करने के लिए ओजस द्वारा

दायर आक्षेपित रिट याचिका संख्या 7123/05 को खारिज कर दिया गया। जबकि औध द्वारा दायर रिट याचिका संख्या 11748/05 को स्वीकार कर लिया गया और मुख्य निदेशक, चीनी द्वारा दिनांक 30.6.05 को पारित आदेश को रद्द कर दिया गया। परिणामस्वरूप, आक्षेपित निर्णय के अनुसार औध द्वारा मैसर्स बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड को खंभारखेड़ा के लिए आईईएम को चुनौती देते हुए दायर की गई रिट याचिका संख्या 12078/05 को भी खारिज कर दिया गया।

12. दिनांक 22.12.05 के आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर ओजस सिविल अपील के माध्यम से इस न्यायालय में आये हैं।

13. आगे बढ़ने से पहले हम बता सकते हैं कि पैरा '63' के तहत दिए गए फैसले में, उच्च न्यायालय ने कहा कि यह केंद्र सरकार के लिए हमेशा खुला है कि वह प्रेस नोट संख्या 12 दिनांक 31.8.98 में संशोधन करे और यह प्रदान करे कि यदि कोई आईईएम दायर किया गया है एक पक्ष द्वारा, तो पहले आईईएम द्वारा बताए गए स्थान के 15 किमी के भीतर चीनी मिल स्थापित करने के लिए अगले आईईएम पर विचार नहीं किया जाएगा। यह अब सटीक रूप से भारत संघ द्वारा किया जाता है। इसने 10.12.06 को गन्ना (नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, 2006 जारी किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आवेदक द्वारा उठाए जाने वाले प्रभावी कदम भी बताए गए हैं। उक्त गन्ना (नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, 2006 ने

गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 में खंड 6 ए से 6 ई को शामिल किया है।  
हम यहां नीचे नए जोड़े गए खंड उद्धृत कर रहे हैं जो इस प्रकार हैं:

“6ए. 15 किलोमीटर के दायरे में दो चीनी मिलों की स्थापना पर प्रतिबंध- खंड 6 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, एक राज्य या दो या अधिक राज्य में किसी भी मौजूदा चीनी मिल के 15 किलोमीटर के दायरे में कोई नई चीनी फैक्ट्री या कोई अन्य नई चीनी फैक्ट्री स्थापित नहीं की जाएगी।

बशर्ते कि राज्य सरकार केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी से, जहां वह सार्वजनिक हित में आवश्यक और समीचीन समझती है, अपने संबंधित राज्यों में विभिन्न क्षेत्रों के लिए 15 किलोमीटर से अधिक की न्यूनतम दूरी या 15 किलोमीटर से कम नहीं अलग-अलग न्यूनतम दूरी को अधिसूचित कर सकती है।

स्पष्टीकरण 1.- एक मौजूदा चीनी कारखाने का मतलब चालू चीनी कारखाना होगा और इसमें एक चीनी कारखाना भी शामिल होगा जिसने चीनी कारखाना स्थापित करने के लिए स्पष्टीकरण 4 में निर्दिष्ट सभी प्रभावी कदम उठाए हैं लेकिन एक चीनी कारखाना शामिल नहीं है जिसने पिछले पांच

चीनी सत्रों के लिए अपने पेराई कार्यों को नहीं किया है।

स्पष्टीकरण 2.- एक नई चीनी फैक्ट्री का मतलब एक ऐसी चीनी फैक्ट्री से होगा, जो मौजूदा चीनी फैक्ट्री नहीं है, लेकिन उसने केंद्र सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा निर्धारित औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन दायर किया है और निर्दिष्ट समय या विस्तारित समय जैसा कि खंड 6 सी में निर्दिष्ट है के भीतर औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन के कार्यान्वयन के लिए मुख्य निदेशक (चीनी), खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को एक करोड़ रुपये की प्रदर्शन गारंटी प्रस्तुत की है।

स्पष्टीकरण 3.- न्यूनतम दूरी भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा मापी गई विधि के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

स्पष्टीकरण 4.- प्रभावी कदमों से तात्पर्य चीनी कारखाने की स्थापना के लिए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन को लागू करने के लिए संबंधित व्यक्ति द्वारा उठाए गए निम्नलिखित कदमों से होगा:-

(ए) कारखाने के नाम पर आवश्यक भूमि की खरीद;

(बी) कारखाने के लिए संयंत्र और मशीनरी की खरीद के लिए पक्का आदेश देना और अपेक्षित अग्रिम भुगतान करना या आपूर्तिकर्ताओं के साथ अपरिवर्तनीय ऋण पत्र खोलना;

(सी) कारखाने के लिए सिविल कार्य और भवन का निर्माण शुरू करना;

(डी) बैंकों या वित्तीय संस्थानों से अपेक्षित सावधि ऋण की मंजूरी;

(ई) इस संबंध में अधिसूचना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कोई अन्य कदम।

6बी. औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन दाखिल करने के लिए आवश्यकताएँ।

(1) केंद्र सरकार के साथ औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन दाखिल करने से पहले संबंधित व्यक्ति गन्ना आयुक्त या निदेशक (चीनी) या निर्दिष्ट प्राधिकरण से प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। संबंधित राज्य सरकार की साइट के बीच की दूरी जहां वह चीनी कारखाने और आसपास के मौजूदा चीनी कारखानों और नए चीनी कारखानों को स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित



न्यूनतम दूरी से कम नहीं है, और संबंधित व्यक्ति को ऐसे प्रमाणपत्र जारी होने के एक महीने के भीतर केंद्र सरकार के पास औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन दाखिल करना होगा, ऐसा न करने पर प्रमाणपत्र की वैधता समाप्त हो जाएगी।

(2) औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन दाखिल करने के बाद, संबंधित व्यक्ति को औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन दाखिल करने के तीस दिनों के भीतर मुख्य निदेशक (चीनी), खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को एक करोड़ रुपये की प्रदर्शन गारंटी जमा करनी होगी। औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन के कार्यान्वयन के लिए एक जमानत के रूप में ज्ञापन, खंड 6 सी में निर्दिष्ट निर्धारित समय या विस्तारित समय के भीतर औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन के कार्यान्वयन के लिए एक जमानत के रूप में ज्ञापन, ऐसा न करने पर इस आदेश के प्रावधानों के अनुसार औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन की मान्यता रद्द कर दी जाएगी।

6C. औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन को लागू करने की समय सीमा. -

प्रभावी कदम उठाने के लिए निर्धारित समय दो वर्ष होगा

और वाणिज्यिक उत्पादन केंद्र सरकार के साथ औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन दाखिल करने की तारीख से चार साल के भीतर शुरू होगा, ऐसा न करने पर जहां तक इस आदेश के प्रावधानों का सवाल है, औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन की मान्यता रद्द कर दी जाएगी और प्रदर्शन गारंटी जब्त कर ली जाएगी:

बशर्ते कि मुख्य निदेशक (चीनी), खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश पर औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन को लागू करने और उसका वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के लिए एक बार में छह महीने से अधिक नहीं एक वर्ष का विस्तार दे सकते हैं।

6डी. खंड 6बी और 6सी में निर्धारित प्रावधानों को लागू न करने के परिणाम- यदि कोई औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन खंड 6 सी में निर्दिष्ट समय के भीतर लागू नहीं होता है, तो संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद इसके कार्यान्वयन के लिए दी गई प्रदर्शन गारंटी जब्त कर ली जाएगी।

6ई. धारा 6बी, 6सी और 6डी का उस व्यक्ति पर लागू होना जिसका औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन पहले ही स्वीकार

किया जा चुका है।-

(1) इस आदेश के खंड 6 बी के उप-खंड (2) में निर्दिष्ट अवधि को छोड़कर, खंड 6 बी, 6 सी और 6 डी में निर्दिष्ट अन्य प्रावधान उस व्यक्ति पर भी लागू होंगे जिनके औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन को इस अधिसूचना की तारीख तक पहले ही स्वीकार किया जा चुका है। लेकिन जिसने खंड 6 ए के स्पष्टीकरण 4 में निर्दिष्ट अनुसार प्रभावी कदम नहीं उठाए हैं।

(2) वह व्यक्ति जिसका औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन इस अधिसूचना की तारीख तक पहले ही स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन जिसने खंड 6 ए के स्पष्टीकरण 4 में निर्दिष्ट प्रभावी कदम नहीं उठाए हैं, वह मुख्य निदेशक (चीनी), विभाग को एक करोड़ रुपये की प्रदर्शन गारंटी प्रस्तुत करेगा। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय इस अधिसूचना के जारी होने के छह महीने की अवधि के भीतर ऐसा न करने पर संबंधित व्यक्ति का औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन इस आदेश के प्रावधानों के संबंध में मान्यता रद्द कर दिया जाएगा।"

14. ओजस की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रेस नोट संख्या 12 में "मौजूदा चीनी मिल" अभिव्यक्ति पर दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा की गई व्याख्या भेदभाव को बढ़ावा देगी। इस संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया था कि यदि किसी मामले में कोई चीनी मिल मौजूद है, जिसका प्रदर्शन खराब है, तब भी उसके 15 किलोमीटर के क्षेत्र में कोई नई चीनी मिल (कारखाना) स्थापित नहीं की जा सकती है। विद्वान वकील के अनुसार, डी-लाइसेंसिंग शुरू करते समय यह इरादा नहीं था। विद्वान वकील ने आगे कहा कि उक्त प्रेस नोट की व्याख्या करने में आक्षेपित निर्णय गलत था। यह आग्रह किया गया कि किसी स्थिति में, भले ही कोई मौजूदा चीनी मिल न हो, कितनी भी चीनी मिलें स्थापित की जा सकती हैं। विद्वान वकील के अनुसार, इस तरह की व्याख्या से न केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत भेदभाव होगा, बल्कि यह क्षेत्र में किसानों के हितों की कीमत पर अक्षम मौजूदा मिलों को सुरक्षा प्रदान करेगा। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि यदि आक्षेपित निर्णय को बरकरार रखा जाता है तो मौजूदा चीनी मिलों को पूर्ण सुरक्षा मिलेगी। उन्हें गन्ने की निरंतर आपूर्ति का आश्वासन दिया जाएगा जबकि उच्च क्षमता के नए चीनी संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखने वाले उद्यमियों को उनकी चीनी मिलों के लिए पर्याप्त गन्ना नहीं मिलेगा। विद्वान

वकील ने प्रस्तुत किया कि आक्षेपित निर्णय चीनी उद्योग में नए निवेश को हतोत्साहित करेगा और परिणाम उदारीकरण की नीति की निराशा होगी। विद्वान वकील ने कहा कि इस तरह की व्याख्या उद्यमी को किसी नए क्षेत्र में चीनी मिल स्थापित करने से पूरी तरह से रोक देगी। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि आक्षेपित निर्णय को बरकरार नहीं रखा जाना चाहिए क्योंकि इससे विनाशकारी परिणाम होंगे। इस संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया था कि आक्षेपित निर्णय के अनुसार जब तक चीनी मिल एक मौजूदा चीनी मिल नहीं बन जाती, तब तक उक्त उद्यमियों को व्यावसायिक प्रतिद्वंद्वियों से कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी, जो निकटता में चीनी मिलें स्थापित कर सकते हैं, जिससे ऐसे उद्यमियों के लिए बुनियादी कच्चे माल की खरीद में मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के प्रावधानों और यूपी गन्ना (आपूर्ति और खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 के प्रावधानों के तहत, गन्ना आयुक्त को चीनी मिलें में गन्ने की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने का उद्देश्य सौंपा गया है। विद्वान वकील ने आग्रह किया कि आक्षेपित निर्णय के कारण किसी भी संख्या में मिलें एक-दूसरे के करीब स्थापित की जा सकती हैं, जिससे गन्ने की मांग इसकी आपूर्ति से बहुत अधिक हो जाएगी और ऐसी स्थिति में गन्ना आयुक्त द्वारा आवंटन बहुत मुश्किल हो जाएगा

क्योंकि वह चीनी मिलों को पर्याप्त गन्ना आवंटित करने की स्थिति में नहीं होंगे। विद्वान वकील ने आग्रह किया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के तहत बनाए गए गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खंड 6 के तहत, केंद्र सरकार को चीनी मिलों को गन्ने की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विनियमन, वितरण और आंदोलन के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार दिया गया है। चीनी मिलों के बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा से बचने और व्यवस्थित तरीके से चीनी की खरीद सुनिश्चित करने के लिए, केंद्र सरकार समय-समय पर दो चीनी मिलों के बीच न्यूनतम दूरी निर्धारित करने वाले प्रेस नोट के रूप में नीति निर्देश जारी करती रही है। इस संबंध में, यह बताया गया कि केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विभिन्न प्रेस नोटों के अवलोकन से पता चलता है कि गन्ने की उपलब्धता के आधार पर दो चीनी मिलों के बीच न्यूनतम रेडियल दूरी हमेशा से बरकरार रखी गई है। विवादित प्रेस नोट संख्या 12 के तहत, शर्त 15 किलोमीटर थी। इसलिए, विद्वान वकील के अनुसार, दो चीनी मिलों के बीच न्यूनतम रेडियल दूरी बनाए रखना आवश्यक था ताकि पहली बार में आईईएम वाली किसी चीनी मिल को कच्चे माल की पर्याप्त आपूर्ति का आश्वासन दिया जा सके। विद्वान वकील ने कहा कि भारत सरकार द्वारा जारी विभिन्न प्रेस नोट्स को पढ़ने से पता चलता है कि दो चीनी मिलों

के बीच की दूरी का गन्ने की उपलब्धता से सीधा संबंध है। विद्वान वकील ने आग्रह किया कि आक्षेपित निर्णय में इन पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया गया है। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने यह कहकर गलती की कि प्रेस नोट संख्या 12 केवल उन मामलों में लागू होगा जहां कोई मिल अस्तित्व (मौजूदा मिल) में है। यह प्रस्तुत किया गया कि इस तरह की व्याख्या से अराजकता फैल जाएगी। यह प्रस्तुत किया गया था कि आक्षेपित निर्णय का परिणाम यह होगा कि चीनी मिलों को नजदीक में स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी जिससे अस्वास्थ्यकर प्रतिस्पर्धा होगी और बुनियादी कच्चे माल की भुखमरी होगी जो मिलों को अव्यवहार्य बना देगी। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि डी-लाइसेंसिंग के बाद भी रेडियल दूरी की शर्त को बनाए रखना आवश्यक था, अर्थात्, एक क्षेत्र में गन्ने की उपलब्धता के साथ संबंध रखने वाली दो चीनी मिलों के बीच पर्याप्त दूरी। इस संबंध में, यह बताया गया कि "दूरी" पिछले 20 वर्षों से एक प्रासंगिक शर्त रही है। यह आग्रह किया गया कि इस शर्त को डी-लाइसेंसिंग के बाद भी बरकरार रखा जाना चाहिए। आईईएम के संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया कि धारा 29बी के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 25.7.91 के तहत 1951 के अधिनियम के अनुसार, डी-लाइसेंसिंग से छूट प्राप्त उद्योगों को आईईएम दाखिल करना पड़ता

था। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि डी-लाइसेंसिंग के बाद भी वही अवधारणा जारी रखी गई है। विद्वान वकील ने बताया कि डी-लाइसेंसिंग के बाद, औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अधिसूचना दिनांक 25.7.91 में सन्निहित आईईएम दाखिल करने की शर्त को बरकरार रखा गया है और इसलिए, इसकी कानूनी पवित्रता और वैधता है। इसलिए, विद्वान वकील ने आग्रह किया कि दूरी की स्थिति न केवल मौजूदा और प्रस्तावित मिल के बीच, बल्कि दो प्रस्तावित मिलों के बीच भी बनाए रखी जानी चाहिए। विद्वान वकील ने आग्रह किया कि एक आईईएम एक उद्यमी को चीनी मिल स्थापित करने के लिए कदम उठाने का अधिकार देता है और आईईएम के बिना कोई भी चीनी मिल स्थापित करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए, विद्वान वकील के अनुसार, प्रेस नोट संख्या 12 दिनांक 31.8.98 के संदर्भ में आईईएम के भाग 'ए' को एलओआई के बराबर किया गया था और आईईएम के भाग 'बी' को औद्योगिक लाइसेंस के बराबर किया गया था। विद्वान वकील के अनुसार, उच्च न्यायालय इस बात को समझने में विफल रहा है कि नए क्षेत्र में स्थापित होने के लिए प्रस्तावित दो चीनी मिलों के संबंध में, केवल आईईएम दाखिल करना पर्याप्त नहीं था, बल्कि प्रभावी कदमों के साथ आईईएम दाखिल करना आवश्यक था। विद्वान वकील के अनुसार, आईईएम



प्लस ऐसे आईईएम को लागू करने के लिए प्रभावी कदम, मुख्य निदेशक, चीनी द्वारा पारित आदेश में बताई गई दोहरी आवश्यकताएं थीं, जिसे उच्च न्यायालय ने गलत तरीके से खारिज कर दिया है। विद्वान वकील ने आग्रह किया कि समय के अनुसार पहले दायर किए गए आईईएम को बाद में दायर किए गए आईईएम पर प्रधानता दी जानी चाहिए, बशर्ते कि पहले आईईएम धारक द्वारा उचित समय के भीतर प्रभावी कदम उठाए गए हों। विद्वान वकील ने आग्रह किया कि जहां पहले आईईएम धारक द्वारा प्रभावी कदम उठाए गए हैं, उसके बाद दायर किए गए अन्य सभी आईईएम और उस स्थान से 15 किमी के भीतर आने वाले को सस्पेंस में रखा जाना चाहिए और यदि पहला आईईएम धारक प्रभावी कदम उठाने में विफल रहता है तो प्राथमिकता दी जानी चाहिए दूसरे आईईएम धारक को वगैरह इत्यादि। विद्वान वकील के अनुसार, निचली अदालत ने इसकी सराहना नहीं की है। उपरोक्त परीक्षणों को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि ओजस ने बैसागापुर में एक चीनी मिल स्थापित करने के लिए 13.5.04 को अपना आईईएम दायर किया था, इसने अपने आईईएम को लागू करने के लिए प्रभावी कदम उठाए थे और इसलिए, विद्वान के अनुसार वकील, औध द्वारा दायर बाद की आईईएम को उच्च न्यायालय द्वारा गैर-स्थायी घोषित किया जाना

चाहिए था। उपरोक्त कारणों से, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि आक्षेपित निर्णय को रद्द करने की आवश्यकता है।

15. दूसरी ओर, औध की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि गन्ना (नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, 2006 दिनांक 10.11.2006 से पहले, एकमात्र प्रतिबंध दूरी के संबंध में था जैसा कि प्रेस नोट संख्या 12 दिनांक 31.8.98 में निहित था। मौजूदा चीनी मिल और नई चीनी मिल (फैक्ट्री) के बीच 15 किलोमीटर की दूरी बनाए रखना आवश्यक था। यह एक आईईएम से दूसरे आईईएम तक नहीं था। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रेस नोट संख्या 12 के तहत एक नई चीनी मिल को स्थापित करने से रोकने के लिए प्रस्तावित चीनी मिल के 15 किलोमीटर के भीतर एक मौजूदा चीनी मिल होनी चाहिए। आदेश में यह आग्रह किया गया है कि किसी मिल को मौजूदा चीनी मिल माना जाए, ऐसे आईईएम को लागू करने के लिए केवल आईईएम या प्रभावी कदम पर्याप्त नहीं थे, बल्कि मिल को मौजूदा चीनी मिल बनना चाहिए था। इसलिए, विद्वान वकील के अनुसार, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया यह दृष्टिकोण 10.11.06 से पहले मौजूद कानून की सही व्याख्या थी। विद्वान वकील ने आग्रह किया कि गन्ना (नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, 2006 जिसके द्वारा खंड 6 ए से 6 ई को गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 में शामिल किया गया था, पूर्वव्यापी नहीं था क्योंकि यह बैंक गारंटी दाखिल करने, दूरी प्रमाणपत्र

दाखिल करने जैसी नई शर्तें निर्धारित करता है और यह आईईएम के कार्यान्वयन के प्रभावी कदम भी बताता है। इसलिए, विद्वान वकील के अनुसार, उक्त गन्ना (नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, 2006, 10.11.06 से पहले प्राप्त स्थिति को प्रभावित नहीं कर सकता है। विकल्प में, विद्वान वकील ने आग्रह किया कि यदि इस न्यायालय का मानना है कि पूर्वोक्त गन्ना (नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, 2006 प्रथम आईईएम धारक के लिए प्रभावी कदम उठाने के अर्थ में नई चीनी मिल स्थापित करने पर रोक लगाता है जहां बाद के आईईएम धारक है, विद्वान वकील के अनुसार, किसी को यह तय करना होगा कि ये प्रभावी कदम क्या हैं और यह निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक तारीख क्या होगी कि प्रभावी कदम उठाए गए हैं या नहीं। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि आईईएम धारक द्वारा उठाए जाने वाले प्रभावी कदम स्पष्टीकरण 4 से खंड 6 ए में निर्धारित किए गए हैं। विद्वान वकील ने इसके अलावा कुछ अन्य प्रभावी कदम भी सुझाए हैं जो एक आवेदक को उठाने चाहिए ताकि बेईमान व्यक्तियों को साइटों को ब्लॉक करने से रोका जा सके। ये हैं कारखाने (मिल) के लिए न्यूनतम 50 एकड़ भूमि की खरीद, कारखाने के लिए संयंत्र और मशीनरी की खरीद के लिए पक्का ऑर्डर देना, अपेक्षित अग्रिम भुगतान या आपूर्तिकर्ताओं के साथ ऋण पत्र खोलना, सिविल कार्य पर कम से कम 25 एकड़ का निवेश, बैंकों/वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋणों की मंजूरी, निधि संसाधनों के विवरण के साथ चीनी कारखाने के लिए परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करना

और एक समय सीमा जिसके भीतर प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए, अन्यथा आईईएम समाप्त हो जाएगा।

16. भारत ने 1991 में आर्थिक सुधार, मुक्त व्यापार और उदारीकरण की नीति अपनाई है। सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं। लाइसेंस राज को चरणों में खत्म किया गया है। तदनुसार चीनी उद्योग को उदारीकृत किया गया है। इसे डी-लाइसेंस कर दिया गया है। इसका उद्देश्य चीनी का उत्पादन बढ़ाना है। इसका उद्देश्य चीनी उद्योग को दुनिया में प्रतिस्पर्धी बनाना है। इसका उद्देश्य व्यवहार्य क्षमता के नए चीनी संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव करने वाले उद्यमियों को गन्ने की निरंतर आपूर्ति करना है। इसका उद्देश्य गन्ने की अनुशासित खरीद और मिलों (कारखानों) को गन्ने की पर्याप्त आपूर्ति करना है। यह अंतिम वस्तु प्रेस नोट संख्या 12 दिनांक 31.8.98 का आधार है। यदि चीनी मिलों को नजदीक में स्थापित करने की अनुमति दी गई तो गन्ने की मांग आपूर्ति की तुलना में बहुत अधिक हो जाएगी और ऐसी स्थिति में मौजूदा चीनी मिलों में गन्ने की कमी हो जाएगी और वे अव्यवहार्य हो जाएंगी, जिसके परिणामस्वरूप किसानों को भी नुकसान होगा।

17. उच्च न्यायालय के समक्ष औध की ओर से की गई दलीलों में से एक यह थी कि 1951 अधिनियम की धारा 29 बी (1) के तहत दिनांक 11.9.98 की अधिसूचना, जिसे प्रेस नोट संख्या 12 दिनांक 31.8.98 के

साथ पढ़ा गया था, मैं पहले आईईएम धारक के सामने बाद के आईईएम धारक के लिए निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर प्रभावी कदम उठाने के लिए किसी रोक का प्रावधान नहीं किया गया था। आक्षेपित निर्णय में (पैरा '65' के माध्यम से) उच्च न्यायालय ने औध के तर्क को स्वीकार करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार प्रेस नोट संख्या 12 में संशोधन करने के लिए स्वतंत्र थी और बाद के आईईएम धारकों के लिए उस स्थान के 15 किलोमीटर के भीतर चीनी मिल स्थापित करने पर रोक का प्रावधान करें जहां पहले आईईएम के तहत प्रस्तावित चीनी मिल स्थापित करने का प्रस्ताव है। जब उच्च न्यायालय ने मामले का फैसला किया तो ऐसी कोई एक्सप्रेस रोक नहीं थी। हालाँकि, गन्ना (नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, 2006 दिनांक 10.11.06 के माध्यम से आईईएम दाखिल करने के बाद प्रभावी कदम उठाने वाले व्यक्ति द्वारा एक नई चीनी फैक्ट्री (मिल) स्थापित करने के लिए खंड 6 ए से 6 ई के तहत एक बार पेश किया गया है। दूसरे शब्दों में, यदि पहला आईईएम धारक या पहले वाला आईईएम धारक अपने आईईएम को लागू करने के लिए प्रभावी कदम उठाता है तो बाद वाला आईईएम धारक अपने आईईएम के साथ आगे नहीं बढ़ सकता है। यदि पहला या पहले का आईईएम धारक अपनी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है तो उस क्षेत्र के लिए शेष आईईएम गैर-अनुमानित हो जाएंगे। हालाँकि, वे निर्धारित अवधि के दौरान संदेह में रहेंगे जब पूर्व आईईएम धारक अपने आईईएम को लागू करने के लिए प्रभावी कदम उठाएगा।

इसलिए, आक्षेपित निर्णय का आधार ही अब समाप्त हो गया है। इसलिए, हमें उक्त निर्णय की वैधता की एक बार फिर से जांच करने की आवश्यकता नहीं है।

18. यह कहने के लिए पर्याप्त है कि गन्ना (नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, 2006 सभी मामलों में पूर्वव्यापी रूप से लागू होगा, जिसमें वर्तमान मामले भी शामिल हैं जिनमें आई. ई. एम. लंबित हैं। इस संबंध में, निर्धारण के लिए जो प्रश्न उठता है वह है: सबसे पहले, क्या गन्ना (नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, 2006 पूर्वव्यापी रूप से लागू होता है और यदि हां, तो क्या स्पष्टीकरण 4 से खंड 6 ए में बताए गए प्रभावी कदम पर्याप्त हैं। इस संबंध में, हमें दूरी प्रमाणपत्र, आईईएम धारक द्वारा उठाए जाने वाले प्रभावी कदमों की अवधारणा और प्रामाणिकता के प्रश्न के बीच वैचारिक अंतर को ध्यान में रखना होगा। गन्ना (नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, 2006 गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खंड 6 में खंड 6 ए से 6 ई सम्मिलित करता है। यह "दूरी" की अवधारणा को बरकरार रखता है। आर्थिक कारणों से "दूरी" की इस अवधारणा को बरकरार रखा जाना चाहिए। यह अवधारणा मांग और आपूर्ति पर आधारित है। इस अवधारणा को बनाए रखना होगा क्योंकि संसाधन, अर्थात् गन्ना, सीमित है। गन्ना कोई असीमित संसाधन नहीं है। "दूरी" का तात्पर्य किसान द्वारा चीनी मिल को आपूर्ति की जाने वाली गन्ने की उपलब्ध मात्रा से है। दूसरी ओर, 1

करोड़ रुपये की बैंक गारंटी दाखिल करना केवल प्रामाणिकता के प्रमाण के रूप में है। एक उद्यमी जो वास्तव में चीनी मिल स्थापित करने में रुचि रखता है, उसे 1 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी देकर अपनी प्रामाणिकता साबित करनी होती है। इसके अलावा, बैंक गारंटी देना भी इस बात का प्रमाण है कि व्यवसायी के पास चीनी मिल (कारखाना) स्थापित करने की वित्तीय क्षमता है। इसलिए, बैंक गारंटी देने का डिस्टेंस सर्टिफिकेट से कोई लेना-देना नहीं है। जहाँ तक प्रभावी कदमों का संबंध है, हम यह इंगित कर सकते हैं कि प्रेस नोट संख्या 12 दिनांक 31.8.98 के साथ पढ़ी गई पिछली अधिसूचना दिनांक 11.9.98 में सूचीबद्ध कदमों के अलावा, गन्ना (नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, 2006 ने कारखाने (मिल) के नाम पर आवश्यक भूमि की खरीद, कारखाने के लिए संयंत्र और मशीनरी की खरीद के लिए एक दृढ़ आदेश की नियुक्ति, आपूर्तिकर्ताओं के साथ अग्रिम भुगतान या ऋण पत्र खोलने, सिविल कार्य और भवन निर्माण का प्रारंभ प्रमाण पत्र, बैंकों या वित्तीय संस्थानों से आवश्यक सावधि ऋण की मंजूरी और इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किसी भी अन्य कदम जैसे कदमों को निर्धारित किया है। हमारे विचार में गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खंड 6 में खंड 6 ए से 6 ई को शामिल किया गया है। हमारे विचार में खंड 6 ए से 6 ई स्पष्टीकरणात्मक प्रकृति के हैं। उद्योग स्थापित करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लेखांकन मानकों में कुछ मानदंड उल्लिखित हैं। वे चीनी मिलें, पेपर मिलें, कपड़ा मिलें आदि हो सकते हैं। जब गन्ना

(नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, 2006 दिनांक 10.11.06 में खंड 6 ए के स्पष्टीकरण 4 के माध्यम से प्रभावी कदम सूचीबद्ध किए गए हैं जो अंतर्निहित मानदंडों को स्पष्ट किया गया है, इसलिए खंड 6 ए का स्पष्टीकरण 4 स्पष्टीकरणात्मक है। इसलिए, यह पूर्वव्यापी है। एक और कारण है कि हम मानते हैं कि गन्ना (नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, 2006 पूर्वव्यापी है। केंद्र सरकार ने गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966, प्रेस नोट संख्या 12 और उक्त 1951 अधिनियम की धारा 29 बी (1) के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 11.9.98 की व्याख्या पर विभिन्न अदालतों में लंबित विभिन्न मामलों पर ध्यान दिया है, और मुकदमेबाजी को समाप्त करने के लिए और "प्रभावी कदम" की अवधारणा से अलग "दूरी प्रमाणपत्र" की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार ने गन्ना (नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, 2006 जारी किया है। इस खामी को दूर करने के लिए ही उक्त आदेश 10.11.06 को जारी किया गया है। इसलिए, हमारे विचार में, गन्ना (नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, 2006 पूर्वव्यापी है। सभी लंबित मामलों में केंद्र सरकार अब एक सीमित अवधि के लिए नई चीनी फैक्ट्री (मिल) स्थापित करने पर रोक लगाना चाहती है, जिसके दौरान पूर्व या पहले के आईईएम धारक को प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता होती है। 2006 का उक्त आदेश नई इकाइयों की स्थापना पर प्रतिबंध नहीं लगा रहा है। यह केवल नई इकाइयों की स्थापना के मामले में प्राथमिकता दे रहा है। यह केवल नई इकाइयों की स्थापना के मामले में प्राथमिकता दे रहा है।



इसलिए, उक्त 2006 का आदेश पूर्वव्यापी रूप से लागू होता है। यह उन मिलों पर लागू नहीं होगा जो पहले से ही काम कर रही हैं। उक्त 2006 का उक्त आदेश केवल उन मामलों पर लागू होगा जहां आईईएम विभिन्न अदालतों में विवादों में लंबित हैं। उक्त 2006 का उक्त आदेश हमारे फैसले के बाद उन मामलों पर भी लागू होगा जो विवाद में हैं और जहां मिलिंग शुरू नहीं हुई है या शुरू करने की अनुमति नहीं है। ओजस की ओर से खंड 6 ए में स्पष्टीकरण 4 में कुछ सुझाए गए संशोधनों का संकेत दिया गया है। वे यहाँ ऊपर बताए गए हैं। वे केंद्र सरकार के विचार के योग्य हैं। यह केंद्र सरकार पर निर्भर है कि वह किसी दिए गए क्षेत्र में गन्ने की उपलब्धता, इकाई की पेराई क्षमता, संयंत्र और मशीनरी की स्थापित क्षमता, गन्ने की उपलब्धता के साथ मिल (कारखाना) की क्षमता उपयोग को ध्यान में रखते हुए ऐसे संशोधनों को शामिल करे जो वह उचित समझे। इस मुद्दे पर निष्कर्ष निकालने से पहले हम दोहरा सकते हैं कि एक इकाई द्वारा संसाधनों को जुटाना और संसाधनों का उपयोग दूरी की स्थिति से अलग है। "दूरी" की अवधारणा "इकाई की स्थापना" की अवधारणा से इस अर्थ में भिन्न है कि एक इकाई की स्थापना व्यवसायी की मुख्य चिंता है जबकि "दूरी" की अवधारणा एक आर्थिक अवधारणा है जिसे सरकार द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए क्योंकि यह सरकार है जिसे आर्थिक नीतियां बनानी होती हैं और जिसे मांग और आपूर्ति जैसे कारकों को ध्यान में रखना होता है।

19. यह आई.ए. इलाहाबाद उच्च न्यायालय (लखनऊ पीठ) में लंबित मामलों से संबंधित है। 2007 का IA नंबर 2 मैसर्स बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड (संक्षेप में, 'बलरामपुर') द्वारा दायर किया गया है। यह कुंभी, जिला लखीमपुर खीरी (यूपी) में अपने कारखाने को मिलिंग की अनुमति देने के लिए है, जो पूरा हो चुका है। बलरामपुर की ओर से कहा गया है कि गन्ना पेराई सत्र हर साल 15 मई तक चलता है। फैक्ट्री मिलिंग शुरू करने के लिए तैयार है। यहां तक कि इसके पक्ष में गन्ना आरक्षण आदेश भी हो चुका है। फैक्ट्री (मिल) तैयार है। बलरामपुर ने 213 करोड़ रुपये का भारी निवेश किया है। बलरामपुर के अनुसार, ओजस का आईईएम भोगोतीपुर के लिए दाखिल किया गया है, केवल इसलिए कि बलरामपुर द्वारा दाखिल आईईएम को रोका जा सके। इसलिए, वे प्रार्थना करते हैं कि बलरामपुर को मिलिंग की अनुमति दी जानी चाहिए और यह न्यायालय उन्हें ऐसी मिलिंग अनुमति प्राप्त करने और लागू करने की अनुमति दे। बलरामपुर के अनुसार, इस न्यायालय को ऐसी अनुमति देनी चाहिए क्योंकि यह गन्ना उत्पादकों, शेयरधारकों और आम जनता के हित में होगा। बलरामपुर के अनुसार यदि ओजस को ऐसी मिलिंग की अनुमति दी जाती है तो इससे उनके साथ कोई पक्षपात नहीं होगा। बलरामपुर के अनुसार, वे कुंभी और गुलेरिया में दो मिलें स्थापित कर रहे हैं और यदि ओजस

भगोतीपुर और बिजुआ में दो मिलें स्थापित करने में असमर्थ है जो क्रमशः कुंभी और गुलेरिया से 15 किलोमीटर के भीतर हैं फिर भी वे आगे बढ़ सकते हैं और लखीमपुर जिले में अन्य मिलें स्थापित कर सकते हैं और, इसलिए, ओजस के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा। कुंभी इकाई पूरी हो गई है। यह मिलिंग गतिविधि के लिए तैयार है।

20. ओजस की ओर से जोरदार तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालयों में मामले लंबित होने के बावजूद बलरामपुर ने कुंभी और गुलेरिया परियोजनाओं में निवेश करने का जोखिम उठाया। यह आग्रह किया गया है कि अंतरिम आदेशों द्वारा बलरामपुर को यह सूचित किया गया था कि वे लंबित रिट याचिकाओं के परिणाम के अधीन कुंभी और गुलेरिया में अपनी उपरोक्त दो परियोजनाओं को लागू करने के लिए स्वतंत्र हैं। यह आग्रह किया गया है कि अदालतों के प्रति सम्मान के कारण, ओजस अपने कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए आगे नहीं बढ़ा, जबकि बलरामपुर ने अपने जोखिम पर कुंभी और गुलेरिया में अपनी परियोजनाओं को लागू करना शुरू कर दिया है। इसलिए, उन्हें नियति का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

21. हमारा विचार है कि कुंभी और गुलेरिया में दो परियोजनाओं में से, बलरामपुर को कुंभी में अपने कारखाने (मिल) के लिए मिलिंग की अनुमति दी जा सकती है। हमारे वर्तमान निर्णय में हमने यह विचार किया

है कि गन्ना (नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, 2006 पूर्वव्यापी रूप से लागू होता है। हमने यह भी विचार किया है कि उक्त 2006 के आदेश को लागू करने में निर्दिष्ट अवधि के दौरान बाद के आईईएम धारकों पर रोक होगी जब पहले आईईएम धारक प्रभावी कदम उठा रहा हो। साथ ही, हम पाते हैं कि कुंभी के मामले में बलरामपुर द्वारा पर्याप्त निवेश किया गया है। उनके अनुमान औध द्वारा स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित इकाइयों से बेहतर हैं। इसके अलावा, गन्ना पेराई सत्र 15 मई, 2007 को समाप्त हो रहा है, हम नहीं चाहते कि गन्ना उत्पादकों को नुकसान हो। इसलिए, हम केवल कुम्भी परियोजना को ही मिलिंग की अनुमति देते हैं। आई. ए. नं. 2 2007 निरपेक्ष बना दिया जाता है। हालाँकि, गुलेरिया परियोजना इस निर्णय में निर्धारित सिद्धांतों द्वारा शासित होगी, जैसा कि ऊपर बताया गया है।

सारांश में:

22. हमारा मानना है कि गन्ना (नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, 2006 पूर्ववर्ती आईईएम धारकों को गन्ना (नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, 2006 दिनांक 10.11.2006 के खंड 6ए के स्पष्टीकरण 4 में विवरणित प्रभावी कदम उठाने के लिए दी गई निर्धारित अवधि के दौरान नई चीनी मिलों (कारखानों) की स्थापना के मामले में बाद के आईईएम धारकों पर प्रतिबंध लगाता है। हम आगे मानते हैं कि उक्त 2006 का आदेश पूर्वव्यापी रूप से

लागू होता है। हमने कुंभी प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय (लखनऊ खंडपीठ) में विभिन्न रिट याचिकाओं में आने वाली अन्य सभी परियोजनाओं का निर्णय इस निर्णय में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

23. सभी सिविल अपीलें, स्थानांतरण याचिकाएँ और अंतर्वर्ती आवेदन तदनुसार लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के निपटाए जाते हैं।

बी. एस

अपील, याचिका एवं आवेदनों का निस्तारण किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी विकास नेहरा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।